web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 14 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 18

छह राज्यों में स्कूली शिक्षा पर जमीनी सर्वेक्षण करा रही है एनसीईआरटी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं पठन-पाठन की व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिये देश के छह राज्यों के छह प्रखंडों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जमीनी सर्वेक्षण करा रही है। यह सर्वेक्षण स्कूलों की स्थिति, पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता, छात्र केंद्रित गतिविधि, शिक्षकों को पेश आने वाली परेशानी, स्कूल के माहौल के आधार पर किया जा रहा है।

एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा इन छह राज्यों में कर्नाटक के मैसूर में हुंसूर प्रखंड, मध्य प्रदेश के भोपाल में इच्छावर, मेघालय के शिलांग में भोइरिमबांग, राजस्थान के भीलवाड़ा में हुर्दा तथा ओडिशा के भुवनेश्वर में चिल्का प्रखंड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन छह प्रखंडों में स्कूली शिक्षा के विविध आयामों पर जमीनी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके तहत हमने कई गतिविधियां तैयार की हैं और इन प्रखंडों में स्थित स्कूलों में इनके अनुपालन को स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा करके और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस सर्वेक्षण के तहत एनसीईआरटी की टीम स्कूलों का दौरा कर रही है और इसमें सामुदायिक भागीदारी भी

सुनिश्चित की गई है। इस कार्य में राज्य शिक्षा विभाग, एससीईआरटी, शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों एवं अधिकारियों की भी सहभागिता है।

एनसीईआरटी के निदेशक ने बताया कि इस सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं पठन पाठन की स्थिति को उन्नत बनाया जायेगा। गौरतलब है कि एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को उन्नत बनाने की योजना बनाई है। एनसीईआरटी के सर्वेक्षण के तहत कर्नाटक के मैसूर में हुंसूर प्रखंड में 329 स्कूलों के 21500 छात्र एवं 1208 शिक्षकों को शामिल किया गया है जबकि मध्यप्रदेश के भोपाल में इच्छावर प्रखंड में 290 स्कूलों में 17000 छात्रों एवं 649 शिक्षकों को शामिल किया गया है। मेघालय के शिलांग में भोइरिमबांग प्रखंड में 183 स्कूलों में 13613 छात्रों एवं 946 शिक्षकों, राजस्थान के भीलवाड़ा में हुर्दा प्रखंड में 167 स्कूलों में 20 हजार से अधिक छात्रों एवं 496 शिक्षकों तथा ओडिशा के भुवनेश्वर में चिल्का प्रखंड में 119 स्कूलों में 16098 छात्रों एवं 574 शिक्षकों को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी के निदेशक ने बताया कि परिषद् ने पहली से आठवीं कक्षा के लिये पहले ही लर्निंग आउटकम जारी कर दिया है और इसी महीने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लर्निंग आउटकम जारी किया जाएगा। सेनापति ने बताया कि हमारा जोर क्षमता उन्नयन पर है। हम छात्रों में समस्या समाधान क्षमता एवं समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। लर्निंग आउटकम को उसी हिसाब से तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्रपति कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी की मां से की मुलाकात

अहमदाबाद (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्द्र मोदी की मां हीरा बा से रविवार सुबह गांधीनगर के निकट उनके घर पर मुलाकात की. गुजरात की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति पत्नी सविता कोविंद के साथ प्रधानमंत्री की मां हीरा बा से रायसन गांव स्थित उनके घर पर मिलने पहुंचे. हीरा बा अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती हैं. उन्होंने उनके साथ करीब आधा घंटा बिताया.

नीदरलैंड के राजा-रानी पांच दिवसीय यात्रा पर आए भारत

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीदरलैंड के राजा विलियम-एलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा अपनी पांच दिवसीय भारत यात्रा पर रविवार को यहां आ गये हैं, जो 14 से 18 अक्टूबर तक की इस यात्रा के दौरान वे द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को लेकर भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। साल 2013 में राजगद्दी संभालने के बाद डच राजा विलियम-एलेक्जेंडर की यह पहली राजकीय भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नीदरलैंड के राजा और रानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। दोनों इस दौरान राजधानी नई दिल्ली, मुंबई और केरल जाएंगे। सोमवार को दोनों राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। नीदरलैंड के राजा और रानी के साथ उनकी कैबिनेट का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

ड्रीमलैंड सिनेमा के पास रिहायशी इमारत में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में चरनी रोड पर ड्रीमलैंड सिनेमा के पास आज सुबह एक रिहायशी बिल्डिंग आदित्य आर्केड में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग घंटे भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग में फंसे लगभग 8 लोगों को बचा लिया गया है। मामूली रुप से झुलसे 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। बताया गया था कि यह लेवल 3 की आग है। इसके बाद फायर ब्रिगेडकर्मियों ने क्रेन और सीढ़ी की सहायता से लोगों को जलती इमारत से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के पहलुओं का अध्ययन करेगा सीसीआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संबंधी विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेगा। दूरसंचार क्षेत्र में हालिया समय में स्थिति में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के कारण यह निर्णय लिया गया है। सीसीआई के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संबंधी पक्षों के अध्ययन की तैयारी शुरू कर दी गयी है। अध्ययन नवंबर में शुरू होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बाजार नियामक होने के नाते हमें इस अध्ययन से पता चलेगा कि हमें किन बातों को लेकर सजग रहना चाहिये और हमें क्या करने की जरूरत है। यह आयोग को प्रतिस्पर्धा को लेकर रणनीति तैयार करने तथा दूरसंचार क्षेत्र को लेकर सुझाव तैयार करने में मदद करेगा। गुप्ता ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं की महत्ता तथा अर्थव्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए यह सीसीआई के लिये जरूरी हो गया है कि वह क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर नजर रखे।

राफेल के बाद अब बढ़ेगी मिग विमानों की ताकत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत को पहला राफेल विमान मिल चुका है। जल्द ही राफेल भारत में आने शुरू हो जाएंगे। राफेल के बाद अब भारतीय वायुसेना रूस से 21 नए मिग-29एस लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोच रही है।

सूत्रों के अनुसार वायुसेना इन लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण कर उन्हें स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस करने की तैयारी में है। इससे ये मिग-29एस लड़ाकू विमान और शक्तिशाली हो जाएंगे। वायुसेना 21 मिग-29एस के अधिग्रहण का प्रस्ताव जल्द ही रक्षा अधिग्रहण परिषद के सामने रखने वाली है। जो मिग-29 इस समय भारतीय वायुसेना के पास हैं उन्हें नए मिग-29एस से अपग्रेड करने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना यह भी चाहती है कि विमान को हवा से हवा में मार करने वाली शस्त्र मिसाइलों/हथियार प्रणालियों से लैस किया जाए। सूत्रों ने कहा कि इस सौदे के बाद विमान को अन्य स्वदेशी उपकरण और हथियारों से लैस किया जाएगा। स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने की खबर ऐसे समय में आई है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वायुसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पांचवीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जैसे स्वदेशी प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करेगा।

पाक ने अब कठुआ में दागे गोले, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

श्रीनगर (आरएनएस)। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। शनिवार को एक बार फिर उसने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए कठुआ के हीरानगर सेक्टर में गोले दागे। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के फायरिंग किया गया। शनिवार को उसने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

बीएसएफ के मुताबिक शनिवार रात से रविवार सुबह 5.30 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी रही।

आज एक राष्ट्र एक फास्टैग पर होगा सम्मेलन

» गडकरी करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह भी राज्य सरकारों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

इस सम्मेलन में देश भर में एक यूनीफायड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लाने के लिए राज्य सरकार के विभागों, अन्य एजेंसियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह विभिन्न राज्यों/एजेंसियों तथा अन्य निकायों के तहत देश में प्रत्येक टोल प्लाजा पर किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर संयोजित समान फास्टैग के उपयोग में सक्षम बनाएगा। यह देश भर में उपभोक्ताओं को अबाधित सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगा।

कल जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम के साथ फास्टैग के समेकन के लिए वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) एवं इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के बीच एक अन्य एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने पहले ही इस समेकन के लिए 'सिद्धान्त रूप से' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। फास्टैग के साथ ईडब्ल्यूबी सिस्टम के समेकन से राजस्व अधिकारियों को, ई-वे बिल जनरेट करते समय वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने कि वे उसी गंतव्य पर जा रहे हैं कि जहां ट्रांसपोर्टर या व्यापारी ने निर्धारित किया था, में मदद मिलेगी।

मामल्लापुरम समुद्र तट पर प्लॉगिंग करते वक्त मोदी के हाथ में था एक्यूप्रेशर रोलर

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. लेकिन इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने चेन्नई के महाबलीपुरम बीच पर प्लॉगिंग की. इस दौरान पीएम मोदी के हाथ में एक उपकरण दिखाई दिया. जिसके बारे में सवाल किए जा रहे थे कि आखिर ये उपकरण क्या था. अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर जवाब दिया है.

पीएम मोदी ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि वह एक्यूप्रेशर रोलर था जिसका वह अक्सर इस्तेमाल करते हैं. पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग के साथ दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए तटीय नगर में मौजूद थे. शनिवार को वार्ता के दूसरे दिन पीएम मोदी को उनकी सुबह की सैर के दौरान समुद्र तट से प्लास्टिक और अन्य तरह का कूड़ा बीनते देखा गया था.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'कल से आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर प्लॉगिंग के वक्त मेरे हाथ में क्या था. वह एक एक्यूप्रेशर रोलर था जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं. मुझे यह बहुत मददगार लगता है.'

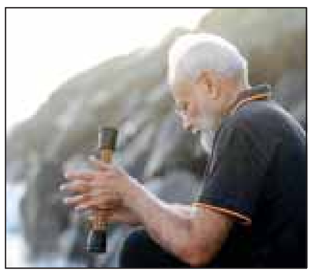

उन्होंने उस एक्यूप्रेशर रोलर की तस्वीरें भी पोस्ट की जो वह समुद्र तट पर लिए खड़े थे. पीएम मोदी ने शनिवार को समुद्र तट पर प्लॉगिंग का अपना तीन मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह कूड़ा उठाते और लोगों से सार्वजनिक स्थानों को साफ एवं स्वच्छ रखने की अपील कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय स्तर का सम्मान

» केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया पुरस्कार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। रविवार को यहां नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटर्नेशनल कॉपरेटिव ट्रेड मेले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट सहकारी राज्य के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने छत्तीसगढ़ हैंडलूम एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन को प्रदान किया। गौरतलब है कि 11 से 13 तीन दिवसीय मेले में छत्तीसगढ़ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट विभाग ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए थे। इस सहकारी मेले में विदेशों से भी

खरीददार काफी संख्या में आए थे। मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और मार्कफेड ने भी स्टॉल लगाया था। मेले में आए आगंतुकों ने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक रंगों से बने कोसे की साड़ी को हाँथों-हाथ लिया। इस मेले में 35 देशों की करीब 150 सहकारी समितियां ने हिस्सा लिया।

दिवाली पर आयुष्मान भारत योजना को प्रमोट करेगी भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा इस दिवाली केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को प्रमोट करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफसे भाजपा के सभी सांसदों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने सभी सांसदों से कहा गया है कि दिवाली पर अपने संसदीय क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ बैठक करें और उनके अनुभव साझा करें। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जहां बीजेपी शासित राज्यों ने इसे लागू किया है वहीं कुछ राज्यों में लगातार इसे लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इससे बेहतर स्कीम दिल्ली सरकार लोगों को मुहैया करा रही है। बीजेपी इस योजना का प्रचार कर रही है। अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सभी सांसदों से इस पर मीटिंग कर इसकी सक्सेस स्टोरी का प्रचार करने को कहा है। सभी सांसदों से कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ मीटिंग करें। उनके अनुभव के बारे में फोटो सहित सोशल मीडिया में जानकारी दें। साथ ही नमो ऐप में भी इस मीटिंग की डिटेल शेयर करने को कहा गया है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी स्कीम को लेकर लगातार सांसदों से मीटिंग कर उन योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने को कहा जा रहा है। मेंबरशिप कैंपेन के दौरान भी अलग अलग स्कीम के लाभार्थियों तक पहुंचने और उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई।

अब बलपूर्वक खाली कराएं जाएंगे पूर्व सांसदों के बंगले

» सरकारी बंगलों पर सांसदों के रिश्तेदार काबिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी आवास में रहने की पात्रता गंवा चुके पूर्व सांसदों से बंगले खाली कराने के साथ आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय सांसदों एवं मंत्रियों के उन अतिथियों से जबरन बंगले खाली कराने की मुहिम तेज करेगा जो लंबे समय से सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं।

शहरी वाकस मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने ऐसे 45 सांसदों, पूर्व सांसदों की लिस्ट तैयार की है जिनके मेहमान तमाम नोटिस के बावजूद बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों की बेदखली के लिये हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 2019 को मंत्रालय द्वारा 12 सितंबर को लागू किये जाने के बाद संपदा निदेशालय ने लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की पात्रता गंवा चुके पूर्व सांसदों और सांसदों के अतिथियों से आवास खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार सूची में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महेन्द्र नाथ पांडे के अलावा पूर्व सांसद संजय सिंह, उदित राज, ओपी यादव और सी पी जोशी के अतिथि भी शामिल हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से पूर्व सांसद जोशी इस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ओपी यादव के अतिथि के रूप में पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पं. पंत मार्ग स्थित सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इसके अलावा सांसद मीनाक्षी

लेखी, रमेश बिधूड़ी और पूनमबेन मादम और अजय टम्टा के अतिथि भी इस लिस्ट में शामिल हैं। गौरतलब है कि किसी सांसद के अनुरोध पर उसके अतिथि को इलाज या अन्य किसी विशिष्ट उद्देश्य से तीन महीने के लिये लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में इस अवधि को तर्कसंगत आधार बताये जाने पर बढ़ाया जा सकता है। निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि 45 अतिथियों की सूची निदेशालय की अर्द्धन्यायिक इकाई के पास भेज दी गयी है।

अधिकारी ने बताया कि पूर्व सांसदों के बंगले खाली नहीं हो पाने के कारण नवनिर्वाचित सांसदों को भी आवास आवंटन में विलंब हो रहा है। लोकसभा की आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि सिर्फ आठ सांसदों को आवास आवंटित होना शेष है और जल्द ही इन्हें भी आवास मिल जायेंगे। हालांकि कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्हें बंगला आवंटन होने के बावजूद आवास खाली नहीं होने के कारण इनको अभी आवास सुविधा नहीं मिल सकी है। इस वजह से राज्यों के भवन और वेस्टर्न कोर्ट सहित अन्य अतिथि गृहों में अस्थायी इंतजाम में इन सांसदों को रहना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार विधि मंत्रालय द्वारा तैनात अर्द्धन्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली इस इकाई ने संबंधित सांसद और उसके अतिथि को नोटिस भेज कर सुनवाई के लिये तलब करना शुरू कर दिया है।